



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2001/कार्तिक 28, 1923

No. 299]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2001/KARTIKA 28, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2001

सं.टीएएमपी/90/2001-विधिव.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कार्गो-संबद्ध प्रभारों के नियतन/संशोधन से संबंधित प्रशुल्क आदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख के संबंध में भारतीय पत्तन संघ के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/90/2001-विधिव

भारतीय पत्तन संघ (आईपीए)

आवेदक

आदेश

(नवम्बर, 2001 के 5वें दिन पारित किया गया)

भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) ने यह सुझाव देते हुए कि जब भी प्राधिकरण कार्गो-संबद्ध प्रभारों के नियतन/संशोधन से संबंधित कोई आदेश पारित करता है, तब इसे आदेश की तारीख के 15 दिनों बाद प्रभावी किया जाए।

2. आईपीए ने यह भी सिफारिश की है कि पोत-संबद्ध प्रभारों के संबंध में कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख वर्तमान के समान अर्थात् आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद 30 दिन की रखी जाए।

3.1 महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 ख (iii) में विहित उपबंधों के अनुसार "प्रत्येक पत्तन में पायलिटिज और कतिपय अन्य सेवाओं अथवा पत्तन देयताओं के लिए शुल्क को बढ़ाने अथवा परिवर्तित करने का आदेश उस तारीख, जिस दिन आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, से 30 दिन की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगा।"

3.2 पायलिटिज और पत्तन देयताएं पोत-संबद्ध प्रभार हैं । पोत-संबद्ध प्रभारों का अन्य मुख्य घटक गोदी किराया है, जो धारा 49 (i) के उपबंध के अधीन नियत किया जाता है । सभी पोत-संबद्ध प्रभारों के कार्यान्वयन के लिए 30 दिन के अग्र समय की अनुमति देने के प्रश्न पर इस प्राधिकरण द्वारा उसकी दिनांक 12 मई, 2000 को हुई बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि सभी पोत संबद्ध प्रभारों के लिए 30 दिनों का अग्र समय निर्धारित करने की व्यवस्था का अनुपालन भविष्य में सभी मामलों में किया जाना चाहिए । तदनुसार, पोत-संबद्ध प्रभारों से संबंधित प्राधिकरण के सभी आदेश सामान्यतः उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी किए जाते हैं ।

4. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अधिनियम की धारा 48 के उपबंधों के अधीन सभी प्रशुल्क नियत करने अथवा वृद्धि/परिवर्तन लागू करने के लिए कोई अग्र समय निर्धारित नहीं करता । सभी कार्गो-संबद्ध प्रभार अधिनियम की धारा 48 के उपबंधों के अनुसार नियत/अनुमोदित किए जाते हैं; और इसलिए ऐसी किसी निर्दिष्ट के अभाव में ये प्रशुल्क सामान्यतः भारत के राजपत्र में संगत आदेश की अधिसूचना की तारीख से लागू किए जाते हैं ।

5. इस प्राधिकरण ने पूर्व में कुछ प्रयोक्ता संगठनों से कार्गो-संबद्ध प्रभारों से संबंधित अपने आदेश की प्रयोज्यता के लिए 30 दिनों के अग्र समय की अनुमति देने के अनुरोध प्राप्त किए हैं । एनएसआईसीटी में कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों के संशोधन से संबंधित अपने आदेश को अधिसूचित करने के बाद प्राधिकरण से कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएसएलए) ने इस संबंध में अनुरोध किया । सीएसएलए ने इंगित किया कि कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों में कोई परिवर्तन करने के पूर्व 30 दिनों का अग्र समय लाइनों को व्यापार जगत को विधिवत नोटिस देने की अनुमति देगा । मुंबई एंड न्हावा शेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन (एमएनएसए) ने भी यह सुझाव देते हुए कि एनएसआईसीटी का संशोधित प्रशुल्क उसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों बाद लागू किया जाए, इस संबंध में ऐसा ही अनुरोध किया ताकि लाइन, व्यापार जगत को पर्याप्त नोटिस देकर अपने टीएचसी को संशोधित करने का अवसर प्राप्त कर सकें ।

6.1 यह मानना होगा कि भारत के राजपत्र में प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना जारी करने की तारीख और उस तारीख, जिस दिन पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करता है, के बीच सदैव एक समयांतराल रहता है । यहां तक कि अधिसूचित आदेश की प्रति की प्राप्ति के बाद भी पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल को संशोधित प्रशुल्क के आधार पर मौजूदा बिलिंग प्रणाली को परिवर्तित करने में कुछ समय लगता है । इसके अतिरिक्त, उसे इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि यह प्राधिकरण उन प्रमुख प्रयोक्ता संगठनों, जिन्होंने कार्यवाहियों में भाग लिया, को आदेश की प्रति अग्रेषित करता है, संशोधित प्रशुल्क के बारे में प्रयोक्ताओं को भी सूचित करना होता है । चूंकि, संशोधित कार्गो-संबद्ध प्रभार भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना पर तत्काल प्रभावी होता है, इसलिए पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल को अनिवार्य रूप से अधिसूचना और ऊपर उल्लिखित विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिलिंग का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का आश्रय लेना पड़ता है ।

6.2 यहां तक कि यद्यपि, यह प्राधिकरण कार्गो/कंटेनर-संबद्ध प्रभारों से संबंधित अपने आदेश को कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख के कारण उत्पन्न हुई बिलिंग संबंधी जटिलताओं से अलग है, फिर भी यह साधारणतया पत्तन न्यास/टर्मिनलों को होने वाली राजस्व हानि पर विचार करते हुए भावी तारीख निर्धारित करने से बचता रहा है । अब आईपीए ने स्वयं सभी महापत्तन न्यासों की ओर से संशोधित कार्गो-संबद्ध प्रभारों के कार्यान्वयन के लिए 15 दिनों के अग्र समय की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है । इसलिए, इस प्राधिकरण को आईपीए द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

6.3 अपने प्रस्ताव में, आईपीए ने बारम्बार आदेश की तारीख का उल्लेख किया है । आदेश की तारीख और अधिसूचना की तारीख के बीच अंतर है । अधिसूचना की तारीख ही वास्तविक है । इस सुधार के अधीन, यह प्राधिकरण कार्गो-संबद्ध प्रभारों से संबंधित अपने आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख के संबंध में आईपीए के सुझाव को स्वीकार करता है ।

7. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण भविष्य में महापत्तन न्यासों से संबंधित सभी मामलों में अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित व्यवस्था, जब तक कि अन्यथा संबंधित आदेश में भिन्न व्यवस्था का उल्लेख न किया गया हो, को अनुमोदित करता है :-

- (i) पोत-संबद्ध प्रभारों से संबंधित इस प्राधिकरण के आदेश जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, सामान्यतया उनकी भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होंगे ।
- (ii) कंटेनर-संबद्ध प्रभारों सहित कार्गो-संबद्ध प्रभारों से संबंधित इस प्राधिकरण के आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होंगे ।

8. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना के तत्काल बाद प्रभावी होगा ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/असा./2001]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2001

No. TAMP/90/2001-Misc.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Indian Ports Association regarding effective date of implementation of tariff Orders relating to fixation/revision of the cargo-related charges as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

No. TAMP/90/2001-Misc.

The Indian Ports Association (IPA)

Applicant

ORDER

(Passed on this 5th day of November 2001)

The Indian Ports Association (IPA) has submitted a proposal suggesting that whenever the Authority passes an Order relating to fixation / revision of cargo related charges, it may be made effective after 15 days of the date of the Order.

2. The IPA has also recommended that in respect of vessel related charges, the effective date of implementation may remain as at present i.e. 30 days after the date of Notification of the Order.

3.1. In accordance with the provisions contained in Section 49 B (iii) of the MPT Act 1963, "an order increasing or altering the fees for pilotage and certain other services or port dues at every Port shall not take effect until the expiration of 30 days from the date on which the Order was published in the official Gazette."

3.2. Pilotage and port dues are vessel related charges. The other main component of vessel related charges is berth hire, which is fixed under the provision of Section 49 (i). The question of allowing 30 days lead time for implementation of all Vessel Related Charges was considered by this Authority in its meeting held on 12 May 2000; and, it was decided that the arrangement of prescribing 30 days lead time for all vessel related charges should be followed in all cases in future. Accordingly, all Orders of the Authority relating to vessel related charges are generally made to come into effect after expiry of 30 days from the date of their publication in the Gazette of India.

4. The MPT Act 1963 does not prescribe any lead time for giving effect to increase / alteration in or fixing of all tariffs under the provisions of Section 48 of the Act. All cargo related charges are fixed / approved in terms of the provisions of Section 48 of the Act; and, therefore, in the absence of any such stipulation, these tariffs are usually made applicable from the date of notification of the relevant Order in the Gazette of India.

5. This Authority has in the past received requests from some of the user organisations for allowing 30 days' lead time for applicability of its Order relating to cargo related charges. The Container Shipping Lines Association of India (CSLA) made a request in this regard after the Authority notified its Order relating to revision of Container Handling Charges at the NSICT. The CSLA pointed out that 30 days lead time before effecting any change in container handling charges would allow the Lines to give due notice to the Trade. The Mumbai and Nhava-Sheva Ship Agents' Association (MANSA) also made a similar request in this regard suggesting that the revised tariff of the NSICT be made applicable 30 days after the same was published in the Gazette of India so that the Lines get an opportunity of revising their THC with adequate notice to the Trade.

6.1. It is to be recognised that there is always a time gap between the date of Notification of the Authority's Order in the Gazette of India and the date on which the Port Trust / Private Terminal receives a copy of such Order. Even after receipt of a copy of the notified Order, a Port Trust / Private Terminal requires some time to change the existing billing system based on the revised tariff. Besides, it has to intimate the users also about the revised tariff, notwithstanding the fact that this Authority forwards a copy of the Order to the major user-organisations that participated in the proceedings. Since the revised Cargo Related Charges come into effect immediately on Notification of the Order in the Gazette of India, a Port Trust / Private Terminal has to invariably resort to retrospective revision of billing for the services provided during the period between the date of Notification and completion of various formalities explained above.

6.2. Even though this Authority is aware of the billing complications arising due to effective date of implementation of its Orders relating to cargo / container related charges, it has generally refrained from prescribing a prospective date considering the revenue loss to the Port Trusts / Terminals. Now the IPA, on behalf of all the Major Port Trusts themselves, has made a proposal to allow 15 days' lead time for implementation of revised Cargo Related Charges. This Authority has, therefore, no objection to accepting the suggestion made by the IPA.

6.3. In its proposal, the IPA has repeatedly referred to the date of Order. There is a difference between the date of order and the date of Notification. What is material is the date of Notification. Subject to this correction, this Authority accepts the suggestion of the IPA in respect of the effective date of implementation of its Order relating to Cargo Related Charges.

7. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following arrangement to be followed in all cases relating to major port trusts in future unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective Orders:

- (i). This Authority's Orders relating to Vessel Related Charges will, unless otherwise stated, ordinarily come into effect after expiry of 30 days from the date of their notification in the Gazette of India.
- (ii). This Authority's Orders relating to Cargo Related Charges, including Container Related Charges, will come into effect after expiry of 15 days from the date of their notification in the Gazette of India.

8. This Order will come into effect immediately after its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman

[Adv./III/TV/143/Exty./2001]

